Enquiry by MRTP Commission

4981. SHRI V. GOPALSAMY : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether MRTP Commission conducted any enquiry into the credentials of 109 private companies which wanted to import, bottle, market, distribute and sell kerosene and LPG in the country; and

(b) if so, the findings in case of each company ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H.R. BHARDWAJ) (a) and (b) Yes, Sir. The Director General of Investigation and Registration has started investigation against 109 private parties who have been allowed to import, bottle, market, distribute and sell kerosene and LPG in the country. The probe letter calling for full information from these 109 parties was issued on 17-2-1994 by way of *suo moto* investigation under section 11(2) of the MRTP Act, 1969. Further action in this regard will be taken by DGI&R after receipt of full information and data from these parties.

Further, the MRTP Commission has also separately directed for undertaking investigations against 12 parties. Out of these, 10 parties are same in respect of which DGI&R has also started investigations.

छत्तीसगढ़ क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय न्यायपीठ की स्थापना किया जाना

4982. **श्री गोविन्दराम गिरी** : क्या **प्रधान मंत्री** 24 फरवरी, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं. 590 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या छत्तीसगढ़ में न्यायपीठ की स्थापना करने के लिए इस क्षेत्र के केन्द्र स्थल बिलासपुर के प्रबल दावे पर ध्यान दिया जा रहा है अथवा न्यायपीठ के गठन के समय बिलासपुर के दावे की उपेक्षा नहीं की जाएगी ?

विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) जसवन्त सिंह आयोग ने, भारत सरकार को अप्रैल, 1985 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के रायपुर और बिलासपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित किए जाने के लिए जनता की मांग की संवीक्षा की थी और उच्च न्यायालय की सिफारिश की थी। अक्तूबर, 1986 में, आयोग की विनिर्दिष्ट सिफारिशें मध्य प्रदेश सरकार की, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करके, उसके विचार जानने और टीका टिप्पणी के लिए भेजी गई थी । उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार के किसी विनिर्दिष्ट प्रस्ताव के अभाव में केन्द्रीय सरकार के लिए इस मामले में आगे कोई कार्रवाई करना संभव नहीं है ।

Changes in the Companies Bill

4983. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether the Associated Chambers of Commerce and Industry of India has urged Government to bring suitable changes in the Companies Bill;

(b) if so, the details of the changes sought;

(c) whether Government proposed to consider the question of brining suitable changes in the Companies Bill; and

(d) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTIC AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H.R. BHARDWAJ) : (a) and (b) Yes, Sir. The Associated Chambers of Commerce & Industry of India have made a number of suggestions for changes in the Companies Bill, 1993 which *inter alia* include classification of Companies, intercorporate loans & investments, Managerial remuneration, remuneration to relatives of Directors, loans to Directors, revision in the rates of deprecia-